While the prospects for the entire country are quite glomy, the situation is much more alarming in Kerala with its low average productivity, poor quality of the product, highest cost of production, heaviest taxburden and incessantly rising wage . And the unavoidable result has been that a good number of estates have already closed down and a growing number is sliding into the red, broken down with unbearable burden of arrears of taxes and wages.

A confrence of the parties was recently convened in New Delhi by the Commerce Ministry and some proposals are reported to have been discussed. But no concrete steps have so far been adopted. The need of the hour is quick adoption and speedy 'mplementation of a comprehensive package of relief measures both by the State Government of Kerala as well as the Centre. Further indecision and delay in this respect is bound to cause irreparable damage to the plantations, especially those in Kerala and result in tens of thousands of workmen and their families who belong to the lowest strata of society being deprived of their only means of livelihood. And let it be remembered, unlike in other industries, the tea estates once closed and left idle will within a short time and turn themselves into jugles entailling colossal expenses for clearing, weeding pruning, manuring, etc. and a waiting period of several weeks to go into production again.

It is time for immediate attention and remedial action on a wide front.

(viii) NEED FOR ABOLITION OF CONTRACTUAL SYSTEM OF *Safai Karmacharis* AND OTHER LABOURERS IN AIR INDIA, BOMBAY

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई में एअर इंडिया के कुछ सफाई मजदूरों एवं अन्य मजदूरों की सम्प्रति आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं सोचनीय है। वे ठेकेदारी प्रथा के शिकार बने हुए है। इन मजदूरों को ठेकेदार द्वारा केवल 7 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाता है जब कि ठेकेदार एअर इंडिया से 25 रुपये प्रति मजदूर भुगतान लेते है। इन असहाय मजदूरों की छुट्टियां काट ली जाती हैं और छुट्टी के दिनों की मजदूरी भी काट ली जाती है। निर्धारित समय से अधिक काम करने पर 1.25 रुपये प्रति मजदूर की दर से अतिरिक्त भुगतान होता है। इस प्रकार उन्हे कुल 225 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन मिलता है। ये मजदूर ठेकेदारों द्वारा रखे जाते हैं। बम्बई जैसे महंगे शहर में 225 रुपये की क्या बिसात है। उच्चाधिकारियों से मिलने पर उन्होंने इस विषय में अपनी अज्ञानता प्रकट की।

एक तरफ तो सरकार मजदूरों के हित के लिए बंधुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त करने का दावा करती है, परन्तु दूसरी तरफ सरकार के ठीक नाक के नीचे किस प्रकार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इस संदर्भ में लिखित रूप से प्रधान मंत्री जी से आग्रह कर चुका हू। उन्होंने आश्वासन भी दिया था किन्तु गहरा दुःख है कि इतने दिनों के बाद 6 महीने के बाद भी इस विषय में कुछ नहीं किया जा सका और एअर इंडिया में यह शोषण क्रूरतम रूप में है।

अतः इस सदन के माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि सफाई मजदूर एवं अन्य शोषित कर्मचारियों के हित में ठेकेदारी प्रथा को यथ शीघ्र समाप्त कर सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा को स्थाई करवाने की कृपा करें।